

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

समस्त जिलाधिकारी (उधमसिंह नगर को छोड़कर),
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक: 12 अगस्त, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को विद्युतीकरण कार्य (अनुसूचित जाति उपयोजना) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या H24/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.2008 एवं वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009, दिनांक 28.07.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को जिला योजनातन्तगत (अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ) अनुमोदित कार्यों हेतु लेखानुदान से शासनादेश संख्या 1011/4(2)/2009-06(1)/104/08, दिनांक 29.04.2009 के द्वारा अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त ऋण के रूप में रु० 2,85,99,000.00 (रु० दो करोड़ पचासी लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण-1 के कॉलम 5 में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार आपके निदर्शन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपदों में वे ही कार्य सम्पादित किये जायेंगे जो चालू योजना के हों एवं जनपद की जिला सैक्टर की योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा चयनित एवं अनुमोदित हैं। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिचय्य सीमा के अधीन ही किया जायेगा। व्यय जनपदवार अनुमोदित प्लॉन परिचय्य के अनुसार ही किया जायेगा तथा उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 24.03.2008 तथा दिनांक 28.07.2009 से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2— कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्य का विस्तृत आगणन, कार्य का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर वास्तविक विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्यों का क्रियान्वयन परियोजना मोड में यथोचित बारचार्ट/पर्ट चार्ट आदि पूर्व में निश्चित कर किया जायेगा।

3— उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, संबंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार कर नियमानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्य एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेंगी।

5- कार्य करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैन्युअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक स्टोर पर्येज तथा शासन के मितव्ययिता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली तथा टेंडर/कंटेनर विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

6- नये कार्या पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- स्वीकृत कार्यों की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

४- आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

9- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रु० 6.5% की दर निर्धारित है। इस ऋण पर भी व्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में (व्याज सहित) माह अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ होगा।

- 10- प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वातचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।
- 11- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करें एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर भेजें:-
- 1- कोषागार का नाम, 2- चालान सं०, 3- जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4- शासनादेश संख्या और एस०एल०आर० का संदर्भ, 5- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।
- 12- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेख से अदृश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।
- 13- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।
- 14- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2010 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रूप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 15- जिला योजना में सामान्य अंश एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ धनराशि अलग से निर्गत है।
- 16- अवमुक्त की जा रही धनराशि का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।
- 17- स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्यय के अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के निचे कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-91-जिला योजना-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं० 515/XXVII(1)/2009, दिनांक 28.07.2009 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या: 1635 /1(2)/2009-06(1)/104/08, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
 - 2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 3- आयुक्त मद्रवाल/कुमाऊँ मण्डल।
 - 4- प्रबन्ध निदेशक/जिला स्तरीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, देहरादून।
 - 5- समस्त जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, उत्तराखण्ड।
 - 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (उधमसिंह नगर को छोड़कर)।
 - 7- वित्त अनुभाग-2/बजट निदेशालय।
 - 8- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण/नियोजन/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 9- प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
 - 10- विशेष सैल, ऊर्जा।
 - 11- गार्ड फाईल हेतु।
- संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)
अनु सचिव

सं.संख्या -30

प्रस्ताविका :- 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

05-पारेषण एवं वितरण - आयोजनागत

190-सरकारकी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

91-जिला योजना

30 निवेश / ऋण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	कुल बजट व्यवस्था	शासनादेश संख्या 1011 दिनांक 29-4-2009 के द्वारा अवमुक्त धनराशि	जिला योजना में अनुसूचित जाति उप योजना में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	नैनीताल	428.99	10.00	20.00
2	अल्मोड़ा		12.67	25.33
3	पिथौरागढ़		9.49	18.97
4	बागेश्वर		1.33	2.67
5	चम्पावत		7.27	14.53
6	देहरादून		15.60	31.20
7	पौड़ी गढ़वाल		18.99	37.97
8	टिहरी गढ़वाल		21.95	43.90
9	चमोली		10.87	21.76
10	उत्तरकाशी		5.40	10.80
11	रूद्रप्रयाग		17.43	34.86
12	हरिद्वार		12.00	24.00
	योग	428.99	143.00	285.99

(रु० दो करोड़ पच्चासी लाख निम्नानुबे हजार मात्र)



12.8.09
(सौरभ जैन)
अपर सचिव